



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 1992/फाल्गुन 7, 1913
No. 36] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 1992/PHALGUNA 7, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह दलगत संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1992

प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण

प्रस्तावना :

सं. एच-11013(2)/90-सी.पी. डब्ल्यू.—1. पर्यावरण के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए प्रदूषण उपशमन के संबंध में सरकार की वचनबद्धता का यहां उल्लेख किया गया है। नीति में वास्तविक कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक समस्या क्षेत्र के उद्देश्यों को परिभाषित करने पर दिए जा रहे बल की पत्राचार द्वारा अवधि कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव विशेष रूप से गरीबों पर पड़ता है। उद्योगों, संगठनों और सरकारी निकायों की संख्या को देखते हुए, जटिलता काफी अधिक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधान और नियंत्रण, वित्तीय प्रोत्साहन स्वैच्छिक समझौतों, शैक्षिक कार्यक्रमों और सूचना अभियानों के रूप में सभी उपायों का अधिकतम उपयोग करना होगा।

इसके लिए विनियमों का अधिक से अधिक उपयोग और वित्तीय प्रोत्साहन के विकास और प्रयोग में वृद्धि पर बल दिया जाएगा।

2. समस्या

2.1 पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। जल चार प्रकार के अपशिष्टों से प्रदूषित होता है। परंपरागत कार्बनिक अपशिष्ट जल, औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, उर्वरकों के लिए रसायनिक एजेंट और फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक तथा अवक्रमित आबाहू क्षेत्रों से गाद। अनुमान है कि उत्पन्न अपशिष्ट जल का 3/4 हिस्सा नगरपालिका स्रोतों से होता है और औद्योगिक अपशिष्टों की मात्रा हालांकि कम होती है, लेकिन ये कुल प्रदूषक भार के आधे से भी अधिक के लिए उत्तरदायी है और इसका अधिकांश हिस्सा बड़े और मझौले उद्योगों से आता है। देश के श्रेणी-1 के नगरों में उत्पन्न कुल अपशिष्ट जल का पांच प्रतिशत से भी कम इकट्ठा किया जाता है और इसके 1/4 से भी कम हिस्से का शोधन किया जाता है।

2.2 प्रमुख नगरों में आसपास का वायु की गुणवत्ता में पता चलता है कि उसमें धूलकणों की मात्रा, विशेषकर गर्मी के

महीनों में, निर्धारित मानकों अथवा सीमाओं से अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों में वाहनों से बढ़ते हुए उत्सर्जन से नाइट्रोजन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है।

2.3 पर्यावरणीय समस्याएँ बहुत रूप धारण करती जा रही हैं। रसायन उद्योगों से निकलने वाले कणों की मात्रा हर वर्ष बढ़ती जा रही है, जिसका वातवरण, मृदा और जल के अनिवार्य पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों के अनिश्चित हमारे समक्ष पर्यावरण के सामाजिक और आर्थिक कार्यों की भी क्षति हो रही है।

2.4 वायु और अपशिष्ट जल में खतरनाक रासायनिक अपशिष्टों को बहाने पर लगे प्रतिबंध के कारण इन अपशिष्टों को भूमि पर फेंका जा रहा है। जो प्रदूषण पहले स्पष्ट अवक्रमणीय था, वह नये किस्म के प्रदूषण का रूप धारण कर रहा है। मंश्लेपित रसायन, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देने, के व्यापक प्रयोग और विपाकता के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। विपाकित रसायनों के खतरों को कम करना अब मूल सार्वजनिक समस्या बन गई है।

2.5 मानव गतिविधियाँ भी वायु मंडल की संरचना को प्रभावित कर रही हैं। अनिश्चितताओं और अपर्याप्त जानकारी के बावजूद भी पर्यावरणीय परिवर्तन से संबंधित राजनैतिक और वैज्ञानिक निर्णय लिए जाने जरूरी होंगे।

2.6 पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती जा रही है, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो जाने से प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव हो गया है। वनों में कमी आने के साथ-साथ प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है, जिसके फल-स्वरूप वातावरण मृदा और जल प्रभावित हुए हैं। कुछ क्षति को तो पूरा किया ही नहीं जा सकता। उच्च जीवन स्तर की तलाश में, जबकि विकसित देशों को अपनी प्रक्रियाओं और उत्पादों में परिवर्तन पर बल देने की आवश्यकता है, विकासशील देशों को अभी भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त करने हैं। इस प्रकार प्रदूषण के उपशमन के संबंध में नीति विवरण, वन नीति विवरण का पूरक है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है, कि प्रत्येक क्षेत्र में उसकी नीतियाँ ऐसे मिश्रणों पर आधारित हों, जिनमें आर्थिक विकास और पर्यावरणीय अपेक्षाएँ दोनों निहित हों।

3. भावी निदेश और उद्देश्य

3.1 अब सरकार के लिए केवल ऐसे नियम अधिसूचित कर देना पर्याप्त नहीं हैं, जिनका कि अनुपालन किया जाना है। प्रदूषण के निवारण के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सही दृष्टिकोण होना अनिवार्य है और अन्तर्गत नीति का कार्यान्वयन करने वाले लोगों के साथ व्यापक परामर्श कर दिलाया गया है।

3.2 विकास आयोजना में पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को समेकित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रदूषण उपशमन के लिए निरोधनात्मक पहलुओं और औद्योगिक प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेशों के संबंधन पर बल दिया जाता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने में जनता के सहयोग पर निर्भर होना पड़ता है।

3.3 उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों के साथ सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को समेकित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपाय किए जाने हैं :

—प्रदूषण का स्रोत पर ही निवारण।

—उपलब्ध सर्वोत्तम व्यावहारिक तकनीकी समाधान को प्रोत्साहन देना उसका विकास और प्रयोग करना।

—यह सुनिश्चित करना कि प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषण और उसके नियंत्रण के प्रबन्ध के लिए जुमाना श्रदा करते हैं।

—अधिक प्रदूषित क्षेत्रों और नदी भागों पर ध्यान केन्द्रित करना, और

—निर्णय लेने में ग्राम लोगों को शामिल करना।

4. नाजुक रूप के प्रदूषित क्षेत्र

4.1 जटिल औद्योगिक स्थलों में प्रदूषकों के जमाव को कम करने के लिए कार्यविधियाँ तैयार की जाएंगी उच्च प्रदूषण भार वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए नीतियों का विकास किया जाएगा, जहाँ सतही पानी के प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के संघी प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। इन क्षेत्रों में मौजूदा इकाइयों में कारगर कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में नई इकाइयों से कड़े पर्यावरणीय स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थल विशिष्ट मानकों का अनुपालन करने के लिए किया जाएगा। इनमें अपशिष्टों के निपटान की समस्या के समाधान के उद्देश्य से अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या के अनुसार ही अपशिष्ट क्रेताओं को रखा जाएगा।

4.2 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना और लघु औद्योगिक एककों की स्थापना में अवसरचना के एक अनिवार्य घटक के रूप में प्रदूषण उपशमन उपाय भी शामिल होंगे। विगत में शोधन सुविधाएँ स्थापित करने और अपशिष्टों के निपटान की व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण कृषि भूमि और नदियों में भारी प्रदूषण फैला है।

4.3 शहरी समुदायों और उद्योगों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि होती रही है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि शहरीकरण, औद्योगिक विकास और जल की बेहतर आपूर्ति के

कारण अपशिष्ट जल की मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। आमतौर पर इस जल को नालों में बहा दिया जाता है अथवा निचले क्षेत्रों में इकट्ठा कर दिया जाता है, भूमि जल संदूषित हो जहाँ किसी प्रकार के शोधन की व्यवस्था नहीं होती। इसमें मलजल इकट्ठा हो जाता है जिससे शहरों के आसपास अच्छी किम्व की भूमि में लवणता आ जाती है। इनसे बदबू आने लगती है और यह मच्छरों और अन्य रोगों के कीड़ों का प्रजनन स्थल बन जाता है। बहुत से स्थानों पर इस जल को इसी तरह की निकास नालों और नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल गम्भीर रूप से प्रदूषित हो जाता है। किन्तु अब इस विषय में जागरूकता आ गई है और अपशिष्ट जल के शोधन के लिए प्रणालियों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। भारत जैसे देश के लिए परम्परागत शोधन संयंत्र बहुत मंहगे पड़ने हैं। वास्तव में, ये साधन बहुत से छोटे कस्बों की वित्तीय पहुँच से बाहर हैं। उपयुक्त वनस्पति आच्छादन के लिए जैवोप अपशिष्ट जल शोधन और भूमि पर निपटान न केवल आकर्षण विकल्प हो सकता है, बल्कि किफायती, सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी हो सकता है।

4.4 सामान्यतया पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक खनन परियोजना के साथ एक खनन योजना भेजी जाए। इसमें एक पर्यावरणीय प्रबंध योजना और पर्यावरणीय क्षति के नियंत्रण और खनिज क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए समयबद्ध सुधार कार्यक्रम भी शामिल है।

5. लघु उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों अपनाने लिए सहायता :

5.1 लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। सरकार लघु उद्योगों के समूह द्वारा उत्पन्न बहिष्कारों और ठोस अपशिष्टों के शोधन के लिए संयुक्त सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। बाद इस योजना के तहत आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

5.2 जबकि बड़े और मझौले औद्योगिक एकक अपने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहेंगे, लघु औद्योगिक एककों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एककों को, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। यह लक्ष्य पर्यावरणीय रूप से अनुकूल जैव प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास करके और उन्हें अपनाकर प्राप्त किया जाएगा।

6. मानक :

6.1 मौजूदा मानक बहिष्कारों और उत्सर्जनों में प्रदूषकों के केंद्रीयकरण पर आधारित हैं। व्यापकता पर आधारित मानक निर्धारित करने के लिए मापदंडों में संशोधन किया

जायेगा, जिनके अनुसार अपशिष्टों में कमी लाने को प्रोत्साहन देने, सामग्रियों के पुनश्चक्रीयन और पुनः प्रयोग को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर जल के संरक्षण के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। क्योंकि ये मानक स्रोत से सम्बद्ध होंगे, इसलिए इनके अनुसार विषाक्त पदार्थों का प्रयोग करने वाले अधिकांश प्रदूषक औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकीय समाधानों और प्रौद्योगिकीय उत्थान के साधनों का प्रयोग करना अपेक्षित होगा।

6.2 भविष्य में सम्भावित समस्याओं का मुकाबला करने के लिए, नई इकाइयों को कठोर मानकों का अनुपालन करना होगा। उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों का चुनाव करने को आवश्यकता होगी, जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न न हो या बहुत कम मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न हो और जिनसे अपशिष्ट उत्पादों का पुनश्चक्रीयन अथवा पुनः प्रयोग हो सके। वाहन यातायात से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों का मुकाबला करने के लिए धार-धार वाहन उत्सर्जन के अधिक कड़े मानक भी तैयार किए जाएंगे।

6.3 मानक केवल नियंत्रक उपाय ही नहीं होंगे, बल्कि प्रदूषण निवारण, संसाधनों के संरक्षण तथा अपशिष्टों के विनियम के लिए प्रौद्योगिकीय उद्यम के संवर्धन के लिए एक कार्यविधि का भी कार्य करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए व्यवहार संहिताएं और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

6.4 खतरनाक और विषाक्त उत्पादों के उत्पादन में निपटान तक जो प्रभाव पड़ता है, उसको विनियम बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा। खतरे के स्तर के अनुसार रसायनों का समीक्षा की जाएगी और जहां सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होंगे, उन रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा विशेषकर खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंध में तथा मृदा और भूमिगत जल के संदूषण के मामले में उपचारात्मक कार्यवाही करने में अधिक ध्यान देने के लिए दायिता विनियम और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के मानक इसके पूरक सिद्ध होंगे।

7. वित्तीय उपाय

7.1 यद्यपि विनियमन उपाय नीति को कारगर बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, बाजार विकल्पों पर विचार करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य उद्योगों और उपभोक्ताओं को पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को लागत के बारे में स्पष्ट संकेत देना है। आशा है कि बाजारोन्मुख मूल्य तंत्र रख को प्रभावित करेंगे ताकि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से बचा जा सके।

7.2 इस समय प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषक उद्योगों को भाँड़भाड़ बाने क्षेत्रों से हटाने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जिन चीजों के लिए

उत्पाद और सीमा शुल्क में छूट दी जाती है उनको समीक्षा की जाएगी। इससे उपशमन प्रौद्योगिकियों का विकास और उत्पादों की अधिक मांग होगी।

7.3 उपचारात्मक उपायों से निरोधात्मक उपायों में परिवर्तन करते, प्रदूषण को लागत को अन्तर्मुखी बनाने और संसाधनों, विशेषकर जल के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक उपायों की जांच की जाएगी। प्रकृति पर आधारित बहिष्काव बाजे और पर्यावरण में विसर्जन को मात्रा द्वारा एक सांघा आर्थिक संकेत दिया जाता है। शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसका स्तर शोधन की लागत और विसर्जित बहिष्काव को मात्रा पर आधारित होगा। प्रभार, उत्सर्जन और टोस अपशिष्टों पर भी लगाए जाएंगे। प्रभार न्यूनतम विसर्जन के लिए एक अविरल प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

7.4 इन उपायों का वितरणात्मक प्रभाव भी होगा, क्योंकि प्राप्त राजस्व का प्रयोग उपायों को लागू करने, संयुक्त शोधन सुविधाओं को स्थापित करने, अनुसंधान और नये पूंजी निवेश के संवर्धन के लिए किया जायेगा।

7.5 अपनाए जाने वाले आर्थिक उपायों का स्पष्ट चुनाव विसर्जन निर्धारण की सुगमता तथा प्रौद्योगिकी और बाजार ढांचे में सम्भावित परिवर्तनों द्वारा किया जाएगा। प्रदूषण को विभिन्न समस्याओं का मुकाबला करने के लिए नियंत्रक और आर्थिक दोनों उपाय किये जायेंगे।

8. समेकन :

8.1 प्रदूषण नियंत्रण के महत्वपूर्ण नौति क्षेत्र सरकार के अलग-अलग विभागों और स्तरों के अन्तर्गत आते हैं। क्षेत्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और विकास परियोजनाओं को आयोजना और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकरणों से पर्यावरणीय मुद्दों को सभी नौति क्षेत्रों में अधिक कारगर तरीके से समेकित करने के लिए कहा जाएगा। स्थानीय प्राधिकारों प्रदूषण के उपशमन में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं और पर्यावरणीय मुद्दों को उनका कार्यविधि में शामिल किए जाने का आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रबंध से संबंधित सरकारी और संस्थागत निकायों को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने होंगे इनमें विशेषकर मंत्रालयों के अधीन आने वाले ऊर्जा, उद्योग, जल संसाधन, परिवहन और कृषि क्षेत्र आते हैं जो प्रदूषण निवारण के लिए विशेष कार्यक्रमों का विकास करेंगे।

8.2 नीति निर्माण, विधान और वानून का कार्यान्वयन परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विनियमों का संख्या में वृद्धि होने पर उन्हें लागू करने में कठिनाइयां बढ़ती हैं। विशिष्ट गतिविधियों के विनियमन के लिए बनाए गए विधान में पर्यावरणीय भागदंड को शामिल करने और उससे होने वाले टकराव को समाप्त करने के लिए विधान में

संशोधन किया जाएगा। अनुपालन पर निगरानी रखने और अपराधों की जांच करने के लिए परस्परगत उपाय अधिक बोझिल होते जा रहे हैं। स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से विकेन्द्रीकृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय नियमों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे को समेकित समीक्षा की जाएगी।

8.3 जबकि कस्बों और उद्योगों सहित विशिष्ट क्षेत्रों से होने वाले प्रदूषण की ओर ध्यान दिया गया है, लेकिन कीटनाशकों, नाशीकीटों, उर्वरक आदि जैसे कृषि निवेशों से होने वाले गैर-स्थानीय प्रदूषण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह समस्या बढ़ती जा रही है और इससे न केवल हमारे जल निकाय ही प्रदूषित हो रहे हैं, बल्कि उप-मृदा जल संसाधन भी प्रदूषित हो रहे हैं और इससे मानव जाति का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। कीटनाशकों के प्रयोग से संबंधित एक दीर्घावधि नीति संबंधित मंत्रालयों के सहयोग में तैयार की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य कीटनाशक, विशेषकर जैव कीटनाशकों और गैर-स्थायी जैव-अवक्रमणीय कीटनाशक के प्रयोग से तथा हानिकारक विषाक्त और स्थायी कीटनाशकों की धीरे-धीरे समाप्ति करना शामिल है और इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उर्वरकों के उपयोग के बारे में भी इसी तरह की नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

8.4 ग्रामतौर पर पौधे और वनस्पति, जलवायु और वातावरणीय समानता को नियंत्रित करके, मृदा संरक्षण और जलीय स्तर को बनाए रखकर प्रदूषण के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, मौजूदा वनों और प्राकृतिक वनस्पति को पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए। जहां भी सम्भव हो, विशेषकर पहाड़ी ढलानों पर, नदियों, झीलों और जलाशयों के आवाह क्षेत्रों में, समुद्री किनारों पर, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में शहरी केन्द्रों और औद्योगिक स्थापनाओं में और उनके आसपास वनों और वनस्पति आच्छादन की बहाली की जाए और जहां संभव हो इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। इस संबंध में यह जरूरी है कि सड़कों, रेल लाइनों और नहरों के दोनों ओर राज्य/निगमित, संस्थागत अथवा निजी स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाए। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों तथा शुष्क क्षेत्रों में हरित पट्टियां बनाई जानी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम से भूमि कटाव और मरुस्थलीकरण भी कम होगा तथा सूक्ष्म वातावरण में सुधार आयेगा।

8.5 मंत्रालयों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों में एक अध्याय नीति विवरण के अनुपालनार्थ की गई कार्रवाई और की गई अथवा प्रस्तावित अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में भी होगा।

9. पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा :

9.1 औद्योगिक संगठनों और स्थानीय निकायों को प्रदूषण कम करने के बारे में अपना दायित्व सहभूम करना चाहिए। स्थानीय निकायों, सांविधिक प्राधिकरणों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की नीतियों, संचालनों और क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव, विशेषकर इन मामलों के अनुपालन और अपशिष्टों के उत्पादन और पुनः प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए उनमें एक पर्यावरणीय विवरण की पद्धति शुरू की जाएगी। वार्षिक विवरण शामिल करने से चिन्ता क्षेत्रों, परिवर्तन की आवश्यकता वाली प्रथाओं और प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए योजनाओं के अभिनिर्धारण और उनकी ओर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी। इसके पश्चात् पर्यावरणीय लेखापरीक्षा शुरू की जाएगी। इस उपाय से लोगों को इस बारे में अधिक जानकारी होगी।

10. पर्यावरणीय आंकड़े :

10.1 विकास संबंधी निर्णय लेने के लिए पर्यावरण के बारे में अधिकृत सांख्यिकीय आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक नीतियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही हैं। इसका संकेत देने के लिए संसाधन लेखांकन का प्रयोग किया जायेगा। मौजूदा आर्थिक लेखे मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हैं, ये लेखे पर्यावरण के संरक्षण पर होने वाले व्यय को नजर अन्दाज कर देते हैं और संसाधनों के अकुशल प्रयोग को प्रोत्साहन देते हैं।

प्रदूषण के प्रभावों की जांच करने के लिए पर्यावरणीय सूचकों की स्थिति के निर्धारण और उनके विकास के लिए पर्यावरणीय, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े इकट्ठे और समेकित किए जाएंगे। पर्यावरण संबंधी सूचना उपलब्ध होना और लोगों को उस सूचना तक पहुंच होनी अनिवार्य है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता लगे कि पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है।

11. जनभागीदारी :

11.1 इस सम्बन्ध में अभिसूचित विकल्प अपनाने के उद्देश्य से जनता को जागरूक करना जरूरी होगा, पर्यावरणीय जोखिम, संसाधनों के अवक्रमण से कार्य और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक लागत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। पर्यावरण के बारे में समय-समय पर सूचना प्रकाशित की जाएगी। पर्यावरणीय निगरानी में प्रभावित नागरिक और गैर-सरकारी संगठन सहस्रपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नियमन प्रणाली में उनकी गह्रायना ली जानी चाहिए तथा इस बारे में उनकी विशेष ज्ञता, अहं हो, को मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी वचनबद्धता तथा सक्रियता भी मूल्यों पर आधारित होगी। जनता को पर्यावरणीय मुद्दों पर नजर रखने के लिए उन्हें इस बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

11.2 जनहित के मुकदमों से सफलतापूर्वक प्रदर्शित हुआ है कि जिम्मेदार गैर सरकारी संगठन और उत्साही व्यक्ति प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर उपशमन उपाय अपनाने के लिए काफी दबाव डाल सकते हैं। इस बचनबद्धता और विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जायेगा और उनके व्यवहारिक कार्य को समर्थन दिया जायेगा।

11.3 उपभोगता छोटे-मोटे योगदानों की अपेक्षा काफी योगदान करने हैं, जिनका कुल प्रभाव काफी होता है। उपभोगताओं में पर्यावरणीय जागरूकता से संबंधित जानकारी देने के लिए "पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल" वस्तुओं को प्रमाण-पत्र देने की एक प्रणाली शुरू की जाएगी। इस मलाह से निर्माणकर्ताओं को पर्यावरणीय रूप से अधिक अनुकूल वस्तुओं को तैयार करने उनके पुनःचक्रण और पर्याप्त अवशिष्ट प्रवन्ध के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उपभोगता संगठनों की सहकारी परीक्षण में भागीदारी द्वारा तथा इन उत्पादों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होने से संबंधित जानकारी के प्रचार से उपभोगता जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

11.4 क्योंकि विविधशास्त्र की वर्तमान प्रणाली में प्रदूषण द्वारा हुई क्षति समेत पर्यावरणीय क्षति के लिए लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है, अब इस कमी को दूर करने तथा अन्तर्गमि राहत के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए भी विविध कानूनी संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

11.5 स्कूल, कालेजों, तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में जागरूकता समझदारी और सक्षमताओं को बढ़ावा देने पर अधिक बल दिया जायेगा। व्यवसायिक और गैर संगठन निकायों को पर्यावरणीय प्रशिक्षण में अधिक सक्रिय बनाने व जागरूकता पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया जायेगा।

11.6 समाज ने उन कई रिवाजों को ग्रहण कर लिया है जिनसे प्रदूषण होता है। लाउडस्पीकों का लापरवाही से प्रयोग, जल निकायों में देर लगाना और अपशिष्टों को बिखेरना आम बात है। भारी शोर के लिए विशेष उपाय करने तथा पड़ोसियों का अधिक ध्यान रखने की अपेक्षा है और यह चिन्ता बढ़ती जा रही है कि हाल के वर्षों में कूड़े-कचरे में वृद्धि हुई है। स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा इन मामलों पर सामाजिक कार्रवाई करने का समर्थन किया जायेगा, जानकारी, शिक्षा, प्रशिक्षण विधियों और जन सूचना अभियानों के जगिण व्यवहार में परिवर्तन लाया जायेगा।

12. यह विवरण वित्तीय संसाधनों की प्रभावकारिता, कुशलता और उपलब्धता के महत्वों पर आधारित है। प्रदूषण उपशमन का दायित्व केवल सरकार का ही नहीं है, बल्कि यह सभी का कार्य है। उपरर्णित नीति में यह दर्शाया जाए

कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त पर्यावरण का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें।

र. राजामणी, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

RESOLUTION

New Delhi, the 26th February, 1992

Policy Statement for Abatement of Pollution

PREAMBLE

No. H. 11013(2)/90-CPW.—I, The commitment of Government on abatement of pollution for preventing deterioration of the environment is stated here. The policy elements seek to shift emphasis from defining objectives for each problem area towards actual implementation, but the focus is on the long term, because pollution particularly affects the poor. The complexities are considerable given the no. of industries, organisations and government bodies involved. To achieve the objectives maximum use will be made of a mix of instruments in the form of legislation and regulation, fiscal incentives, voluntary agreements, educational programmes and information campaigns. The emphasis will be on increased use of regulations and an increase in the development and application of financial incentives.

2. THE PROBLEM :

2.1 There is an increasing trend in environmental pollution. Water is polluted by four kinds of substances; traditional organic waste, waste generated from industrial processes, chemical agents for fertilisers and pesticides for crop protection and silt from degraded catchments. While it is estimated that three-fourths by volume of the waste water generated is from municipal sources, industrial waste, though small in volume, contributes over one-half of the total pollutant load, and the major portion of this is coming from large and medium industries. For class-I cities of the country, less than five per cent of the total waste water generated is collected and less than one-fourth of this its treated.

2.2 Ambient air quality trends in the major cities indicate that levels of suspended particulate matter are higher than the prescribed standards or limits, especially in summer months. Levels of nitrogen dioxide are increasing in urban centres with growing vehicle emissions.

2.3 Environmental problems are becoming larger in scale. The chemical industry generates an increasing quantity of substances every year; adversely affecting essential aspects of the composition of the atmosphere, soil and water. In the industrial high density areas, in addition to the effects on local health and impact on nature, we are confronted with damage to the social and economic functions of the environment.

2.4 With restrictions on releases to air and waste water hazardous chemical wastes are getting diverted to land for their disposal. Earlier concerns with pollution that was visible and degradable are giving way to new types of pollution with very small quantities of synthetic chemicals that are not so visible and are injurious to health and damage the environment because of widespread use, persistence and toxicity. Reducing the hazards from toxic chemicals is now a primary public concern.

2.5 Human activities are also influencing the composition of the atmosphere. Despite uncertainties and insufficient knowledge, political and scientific decisions concerning environmental change will increasingly be necessary.

2.6 The state of the environment continues to deteriorate. The growth in scientific and technical knowledge has made

it possible to use an ever increasing quantum of natural resources. The increase in population is further enhancing the pressure on the environment. The depletion of forests has been accompanied by increasing amount of pollution affecting atmosphere, soil and water. Some of the damage is irreversible. In seeking a higher quality of life while developed countries need to focus on changing the composition of their processes and products, developing countries will need to obtain the benefits of economic growth. The policy statement on Abatement of Pollution thus complements the Forest Policy Statement. The Government seeks to ensure that its policies in every sector are based on a set of principles that harmonise economic development and environmental imperatives.

3. FUTURE DIRECTIONS AND OBJECTIVES

3.1 It is not enough for the Government to notify laws which are to be complied with. A positive attitude on the part of everyone in society is essential for the prevention of pollution and wide consultation has been held with those who will ultimately implement the policy.

3.2 A comprehensive approach is taken to integrate environmental and economic aspects in development planning; stress is laid on preventive aspects for pollution abatement and promotion of technological inputs to reduce industrial pollutants; and through reliance upon public cooperation in securing a clean environment to respond to the coming challenges.

3.3 The objective is to integrate environmental considerations into decision making at all levels. To achieve, this steps have to be taken to :

- prevent pollution at source;
- encourage, develop and apply the best available practicable technical solutions;
- ensure that the polluter pays for the pollution and control arrangements;
- focus protection on heavily polluted areas and river stretches; and
- involve the public in decision making.

4. CRITICALLY POLLUTED AREAS

4.1 Mechanisms will be evolved to reduce local concentration of pollutants in complex industrial sites. Strategies will be developed for areas with high pollution loads where the accumulative effect of the various types of pollutants would be taken into account including pollution of ground water. Existing units in these areas will be targeted for effective action. New units in these areas will be required to comply with location specific standards for stringent environmental quality objectives. These will include matching waste generators with waste buyers, with the objectives of solving waste disposal.

4.2 Setting up of industrial estates, and clusters of small industrial units in rural areas, will include pollution abatement measures as an essential component of infrastructure. In the past, the absence of adequate provision of space for installing treatment facilities and arrangements for disposal of wastes has led to severe pollution of agricultural land and rivers.

4.3 There has been a steady increase in the amount of waste water produced from urban communities and industries. In the coming years, due to rapid growth in population, urbanisation, industrial development and better water supply, the amount of waste water may increase manifold. Generally, these waters are discharged into lagoons or dumped on low lying areas without any pre-treatment, thereby creating sewage pools, contaminating ground waters, salinizing good quality lands around cities, acting as a source of foul smell and breeding grounds for mosquitoes and other pathogens. At many places this waste water is discharged into drains and rivers causing serious water pollution. However, awareness has now grown and more attention is being paid to develop systems to treat sewage waters. For a country like

India, conventional treatment plants are costly. In fact, these are beyond the financial means of many small towns. Biological waste water treatment, on-land disposal using suitable vegetative cover and resource recovery technologies cannot only be attractive alternative, but also economical, safe and socially acceptable.

4.4 Mining operations will not ordinarily be taken up in ecologically fragile areas. Every mining project shall be accompanied by a mining plan, including an environmental management plan and time bound reclamation programme for controlling the environmental damage and for restoration of mined areas.

5. ASSISTANCE FOR ADOPTION OF CLEAN TECHNOLOGIES BY SMALL SCALE INDUSTRIES:

5.1 Small scale industries are a special feature of our economy. Government are implementing a scheme for providing assistance for promoting combined facilities for treatment of effluents and solid wastes generated in clusters of small scale units. This scheme will be extended to provide necessary technical support as well.

5.2 While the large and medium industrial units will remain totally responsible for control of their pollution, assistance will be provided to small scale industrial units, particularly those located in rural areas, to aid the implementation of pollution control measures. This will be achieved by promoting development and adoption of cleaner technologies, including environmentally friendly biotechnology.

6. STANDARDS

6.1 The present standards are based on the concentration of pollutants in effluents and in emissions. The norms will be revised to lay down mass-based standards, which will set specific limits to encourage the minimisation of waste, promote recycling and reuse of materials, as well as conservation of natural resources, particularly water. Since the standards will be source related, they will require for the most polluting industrial processes, particularly those using toxic substances, application of the best available technological solutions, and also be an instrument for technological upgradation.

6.2 To act against potential problems in the future, new units will have to conform to stricter standards. They will need to select technologies that produce no or low quantities of wastes and recycle or reuse waste products. Progressively, more strict vehicle emission standards will also be evolved to deal with environmental hazards caused by vehicular traffic.

6.3. Standards will not merely be a regulatory tool but will be mechanism to promote technological upgradation to prevent pollution, conserve resources and regulate waste. For this purpose codes of practice and guidelines will be evolved for specific processes.

6.4 The environmental effects, from production to disposal of products that are hazardous and toxic will be taken into account in the regulations. Chemicals will be reviewed according to the level of risk, and where safer alternatives have become available, restrictions will be imposed. Regulations for liability and compensation for damages will supplement standards, to promote greater care and caution, particularly in the management of hazardous waste and remedial action in case of contamination of soil and ground water.

7. Fiscal measures.

7.1 While regulatory measures remain essential for the effectiveness of the policy, new approaches for considering market choices will be introduced. The aim is to give industries and consumers clear signals about the cost of using environmental and natural resources. The expectation is that market-oriented price mechanisms will influence behaviour to avoid excessive use of natural resources.

7.2 There are at present several fiscal incentives for installation of pollution control equipment and for shifting polluting industries from congested areas. The items for which excise and customs rebate are allowed will be reviewed. This will stimulate the advancement of abatement technologies and create increased demands for the products.

7.3 Economic instruments will be investigated to encourage the shift from curative to preventive measures, internalise the costs of pollution and conserve resources, particularly water. A direct economic signal is offered by an effluent charge based on the nature and volume of releases to the environment. The level will be based on the cost of treatment and the flow discharged, in order to provide an incentive to set-up treatment plants. The scope of the charges will also be extended to emissions and solid waste. Charges provide a continuing incentive towards optimal releases.

7.4 These instruments will also have a distributive effect as the revenues will be used for enforcement, collective treatment facilities, research and promoting new investment.

7.5 The precise choice of economic instruments adopted will be determined by the ease with which releases can be measured, as well as prospective changes in technology and market structures. To deal with the range of pollution problems a mix of regulatory and economic measures will be adopted.

8. Integration.

8.1 Critical policy areas for control of pollution come under different departments and levels of Government. Sectoral Ministries, State Governments, local bodies and agencies responsible for planning and implementation of development projects will be required to integrate environmental concerns more effectively in all policy areas. Local authorities play a key role in abatement of pollution and environmental concerns need to be built into the way they operate. Steps will have to be taken to strengthen governmental and institutional structures dealing with environmental management, especially within the ministries dealing with the sectors of energy, industry, water resources, transport and agriculture, and who would develop specific programmes in regard to pollution prevention.

8.2 Policy making, legislation and law enforcement influence each other. The increase in the number of regulations increase difficulties in enforcement. Legislation regulating particular activities will be amended to incorporate and eliminate clashes with environmental criteria. Traditional instruments for monitoring of compliance and investigation of offences are becoming overburdened. An integrated overview and organisational structure for decentralised environment impact assessments and environmental law enforcement based on cooperation with local authorities will be sought.

8.3 While pollution from specific sources including towns and industries have been addressed, non-point pollution from run-off of agricultural inputs such as pesticides, insecticides, fertilisers, etc. has not been dealt with. This is gaining increasing proportions, which is polluting not only surface water bodies but even sub-soil water resources and would affect the health of human beings. A long-term policy for pesticides use, including the introduction of environmentally acceptable pesticides, particularly biopesticides and non-persistent biodegradable ones, and integrated pest management together with the phasing out of the proven harmful toxic and persistent ones, would be formulated in collaboration with the concerned Ministries and infrastructure involved for its effective implementation. A similar policy for fertiliser use will also need to be formulated.

8.4 Plant and vegetation in general play a vital role in controlling pollution by regulating the climate and atmospheric equilibrium, protecting the soil and maintaining the hydrological regime. Hence, existing forests and natural vegetation should be fully protected. The forest and vegetal cover should be restored and increased wherever possible, specially on hill slopes, in catchment areas of rivers, lakes and reservoirs, ocean shores, semi arid and arid tracts, in

and around urban centres and industrial establishments. It is necessary to encourage the planting of trees alongside roads, rail lines, canals and on other unutilised lands under state/corporate, institutional or private ownership. Green belts should be raised in urban and industrial areas as well as in arid tracts. Such a programme will also check erosion, desertification as well as improve the micro-climate.

8.5 The Annual Administration Reports of the Ministries will include a chapter on the action taken to follow up the policy statement, and other environmental initiatives they have taken or are proposing.

9. Environmental Audit.

9.1 Industrial concerns and local bodies should feel that they have a responsibility for abatement of pollution. The procedure of an environmental statement will be introduced in local bodies, statutory authorities and public limited companies to evaluate the effect of their policies, operations and activities on the environment, particularly compliance with standards and the generation and recycling of waste. An annual statement will help in identifying and focussing attention on areas of concern, practices that need to be changed and plans to deal with adverse effects. This will be extended to an environmental audit. The measures will provide better information to the public.

10. Environmental Statistics.

10.1 Authoritative statistical data on the environment is vital for Developmental decision making. Resource accounting will be used to give an idea how economic policies are affecting the environment. Current economic accounts are concerned mainly with the volume of economic activity; they ignore expenditures to protect the environment and encourage inefficient use of resources.

The collection and integration of environmental, economic and health data will be done to determine the status and to develop a concise set of environmental indicators for monitoring the effects of pollution. Information and access to the public are essential so that everyone knows what is happening to the environment.

11. Public Partnership.

11.1 The public must be made aware in order to be able to make informed choices. A high governmental priority will be to educate citizens about environmental risks, the economic and health dangers of resource degradation and the real cost of natural resources. Information about the environment will be published periodically. Affected citizens and non-governmental organisations play a role in environmental monitoring and therefore allowing them to supplement the regulatory system and recognising their expertise

where such exists and their commitments and vigilance, will also be cost effective. Access to information to enable public monitoring of environmental concerns, will be provided for.

11.2 Public interest litigation has successfully demonstrated that responsible non-governmental organisations and public spirited individuals can bring about significant pressure on polluting units for adopting abatement measures. This commitment and expertise will be encouraged and their practical work supported.

11.3 Householders, as consumers, make large number of relatively small individual contributions, whose cumulative effect is considerable. A system of certification of goods that are "environmentally friendly" will be set up to make available information to encourage environmental consciousness amongst consumers. This advice will also encourage manufacturers to produce goods that are environmentally more friendly as well as encourage recycling and adequate waste management. Consumer awareness would also be encouraged by involvement of consumer organisations in cooperative testing, and dissemination of information relating to environmental friendliness of these products.

11.4 As the present system of jurisprudence does not provide for compensation to individuals for environmental damage, including effects on health and environmental damage caused by pollution, it is proposed to set up special legal institutions to redress this deficiency and also make adequate arrangements for interim relief.

11.5 Greater emphasis will be placed on promoting awareness, undertaking and competence in schools, colleges, and training institutions. Professional and non-governmental bodies will be encouraged to be more active in environmental training and building awareness.

11.6 Society has accepted many practices which cause pollution. Reckless use of loudspeakers, dumping in water bodies, and scattering of wastes are common. Noise nuisance requires specific devices as well as greater consideration for neighbours and there is growing concern that litter has increased in recent years. Social action in these matters by voluntary organisations and individuals will be promoted through knowledge, education, training camps and public information campaigns.

12. This statement is based on considerations of effectiveness, efficiency and availability of financial resources. The responsibility for abatement of pollution is not a duty of the Government alone, it is an obligation on all. The approach mentioned above should indicate how every one can help in achieving a safe and environmentally appropriate environment in our country.

R. RAJAMANI, Secy.